

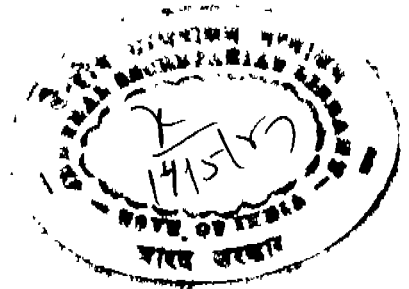


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 71]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 1987/माघ 21, 1908

No. 71]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 1987/MAGHA 21, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

इम्पान और खान सचिवालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1987

अधिसूचना

सा. वन. नि. 86(अ) :- केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (वित्तियम और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के धारा 13 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में -

(1) नियम 4, 4क, 5, 6, 7 और 7क का शेष किया जाएगा।

(2) नियम 9 के उपनियम (2) में -

(i) खंड (ख) और (ग) का शेष किया जाएगा।

(ii) खंड (ग) के पश्चात् किन्तु प्रथम परन्तु क से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतर्स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(उ) कोई शपथ पत्र यह कथन करने हुए, कि आवेदन ने;

(i) अद्यतन आय-कर विवरणियां भरी है,

(ii) उस पर निर्धारित आय-कर संदाय कर दिया है, और

(iii) आय-कर अधिनियम, 1961 में यथा उपबंधित स्वयं निर्धारण के आधार पर आय-कर का संदाय कर दिया है,

(च) प्रत्येक राज्य में, खनिजवार क्षेत्रों की विनिर्दिष्ट प्रशंसित करने हुए, कोई ऐसा शपथ पत्र, जिसे आवेदन या उसके साथ संयुक्त रूप से कोई व्यक्ति -

(i) किसी पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति के अधीन पहले से ही धारण कर रहा है,

(ii) उसके लिए आवेदन किया गया किन्तु मंजूर नहीं किया गया है,

(iii) उसके लिए साथ-साथ आवेदन किया है।

(छ) लिखित रूप में यह कथन किया गया है कि आवेदक ने,

जहाँ भूमि उसके स्वामित्व में नहीं है, उस क्षेत्र में भूमतह अधिकार प्राप्त कर लिया है या पूर्वोक्त सन्धिपूर्ण प्रारम्भ करने के लिए स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है। परन्तु, ऐसा कोई कथन वहाँ आवश्यक नहीं होगा जहाँ भूमि सरकार के स्वामित्व में है।

(ii) प्रथम परन्तु क में "खनन शब्दों के पश्चात्" "या आय-कर संबंधी शोध" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. नियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"10-क ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जब भारतीय राष्ट्रिक नहीं है केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, किसी खनिज को वास्तव कोई पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति मंजूर या नवीकृत नहीं की जाएगी।"

4 नियम II के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2)(क) पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति के नवीकरण का आवेदन, पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति के अवसान से कम से कम नब्बे दिन पूर्व किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होगा :-

(i) आवेदक द्वारा पहले ही आरम्भ किए गए पूर्वोक्त सन्धियाओं से संबंधित कोई कथन ;

(ii) उपगत व्यय की रकम ;

(iii) बंटों और दिनों का संख्या जिनमें कार्य किया गया, और

(iv) वह अवधि जो पूर्वोक्त कार्य को पूरा करने के लिए आवेदित है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा किसी पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति के नवीकरण के आवेदन का निपटारा पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति के अवसान की अवधि से पूर्व किया जाएगा और यदि आवेदन का निपटारा उस अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो, अनुज्ञप्ति को, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए विहित अवधि से अनधिक अवधि के लिए या उस अवधि के लिए जिसके लिए आवेदन किया गया है, जो भी कम हो, नवीकृत किया गया समझा जाएगा।"

5 नियम 12 के उपनियम (1) में,

"राज्य सरकार," शब्दों को पश्चात्, "मुनवाई के अवसर दिए जाने के पश्चात्" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6 नियम 14 के उपनियम (1) में, खंड (ii) के पश्चात् किन्तु परन्तु से पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :

"(iii) अनुज्ञप्तिधारी, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन समय-समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का संशय नहीं करेगा,

(ix) अनुज्ञप्तिधारी खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों का अनुपालन करेगा ;

(x) अनुज्ञप्तिधारी, उसी क्षेत्र में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा चुने गए किसी अन्य क्षेत्र में, किसी पूर्वोक्त सन्धि के कारण नष्ट हुए वृक्षों की संख्या के दो गुने से अधिक वृक्ष या उस विस्तार तक जो संभव हो, वृक्षारोपण एवं सन्धियाओं द्वारा नष्ट हुई पुष्प वनस्पति और अन्य वनस्पतियों के पुनः स्थापन के लिए अपने खर्च पर ऐसे उपाय करेगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देश दिया जाएगा।

(xi) अनुज्ञप्तिधारी, भूमि के मतह के अधिकारी को ऐसे प्रतिफल का संदाय करेगा जो इन नियमों के अधीन संवेद्य हो ;

(xii) अनुज्ञप्तिधारी धारा 18 के अधीन विरचित खनिज संरक्षण और विकास नियमों का पालन करेगा।"

7. नियम 22 के उपनियम 3 के खंड (i) से-

(i) उपखंड (ख) और (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपखंड (घ) में, प्रथम पुस्तक से पहले निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ;

"(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्पन्न रूप से अनुमोदित कोई खनन रेखांक 1 खनन रेखांक में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

(1) खनिज निकाय का विस्तार उस स्थल या उन स्थलों को जहाँ प्रथम बार में उखनन किया जाता है और उसके विस्तार को दर्शाते हुए क्षेत्र का रेखांक, विस्तृत वर्गीकृत आंकड़े और आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इकट्ठे किए गए पूर्वोक्त आंकड़ों के आधार पर उखनन के स्थल (स्थलों) के विस्तृत रेखांक पट्टे के प्रथम पांच वर्षों के लिए खनन की कोई प्रतिम स्कीम ;

(ii) क्षेत्र की खनिज आरक्षितियों सहित भूविज्ञान और आग्नि की के ब्लोरे ;

(iii) श्रमिक खनन या मशीनरी और यांत्रिक युक्तियों के उपयोग द्वारा खनन ;

(4) प्राकृतिक जल मार्ग, यन क्षेत्र और वृक्षों की सघनता यदि कोई हो, वनों में खनन क्रियाओं के समाधान, भूमि मतह और वायु तथा जलप्रदूषण सहित पर्यावरण दूषित करने वाले क्षेत्र का रेखांक ; वृक्षारोपण भूमि पुनरुद्धार द्वारा क्षेत्र के पुनःस्थापन के लिए स्कीम के ब्लोरे, पर्यावरण नियंत्रण तकनीकों का उपयोग, और ऐसे अन्य उपाय जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किए जाएंगे ;

(5) अन्य कोई पदार्थ जिसके लिए केन्द्रीय सरकार आवेदक में व्यवस्था करने की उपेक्षा कर सकेगी।

(ख) कोई शपथ पत्र यह कथन करते हुए कि आवेदक ने, -

(i) खनन आय-कर विवरणियाँ भरी हैं,

(ii) उस पर निर्धारित आय कर संदाय कर दिया है ; और

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 में यथा उपबंधित स्वयं निर्धारण के आधार पर आय-कर का संदाय कर दिया है ;

(छ) प्रत्येक राज्य में, खनिजधार क्षेत्रों की विनिर्दिष्टां दर्शाते करते हुए कोई ऐसा शपथ पत्र जिसे आवेदक या उसके साथ संयुक्त रूप से कोई व्यक्ति-

(i) किसी पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति के अधीन पहले से ही धारण कर रहा है ;

(ii) उसके लिए आवेदन किया है किन्तु मंजूर नहीं किया गया है ; और

(iii) उसके लिए साथ-साथ आवेदन करेगा है।

(ज) लिखित रूप में यह कथन किया गया है कि आवेदक ने, जहाँ भूमि उसके स्वामित्व में नहीं है, उस क्षेत्र में भूमतह अधिकार प्राप्त कर लिया है या पूर्वोक्त सन्धियाएँ प्रारम्भ करने के लिए स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है, परन्तु, ऐसा कोई कथन वहाँ आवश्यक नहीं होगा जहाँ भूमि सरकार के स्वामित्व में है।"

8. नियम 22 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“22ख खनन संचालन, खनन रेखांक के अनुसार होगी।

- (1) खनन सुविधाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित खनन रेखांक के अनुसार की जाएगी।
- (2) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खनन पट्टे को संचालन दोरान कोई खनन रेखांक पर क्वाटरन की जा सकेगा।

22ख खनन रेखांक मान्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाएगा :—

- (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी रेखांक का तब तक अनुमोदन नहीं किया जाएगा जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार न किया गया हो।
- (2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास —

- (i) किसी केन्द्रीय अधिनियम, किसी प्रान्तीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या नियमित किसी विश्वविद्यालय द्वारा जिसे अतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्था भी है, प्रदान की गई खनन इंजीनियरी में कोई डिग्री या भूविज्ञान में कोई स्नातकोत्तर डिग्री न हो या भारत से बाहर किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदान की गई कोई समतुल्य प्रहता न हो और
- (ii) डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् खनन संचालन में किसी पर्यवेक्षणीय हैसियत में कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव न हो।

- (3) खनन रेखांक तैयार करने के लिए मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति खनन रेखांक में उपांतरण भी कर सकेगा।

22ग. केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता देना।

- (1) नियम 22ख के उपनियम (2) में निविष्ट अर्हताएं और अनुभव रखने वाला व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को, किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा।
- (2) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, मान्यता की मंजूरी दे सकेगा या इंकार कर सकेगा और जहां मान्यता देने से इंकार किया जाता है, वहां सक्षम प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे और उन्हें आवेदक को संसूचित किया जाएगा।
- (3) ऐसी कोई मान्यता दो वर्षों की किसी आरंभिक अवधि के लिए दी जाएगी और वैसे ही अवधि के लिए स्वीकृत की जाएगी : परंतु सक्षम प्राधिकारी संवर्धन व्यक्ति को युतबाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसे कारणों से जा लेखबद्ध किए जाएंगे, मान्यता नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा।
- (4) मान्यता के लिए किसी आवेदन को मंजूर या नवीकृत करने से इंकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आवेदन के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील की जाएगी।

स्पष्टीकरण

इस नियम के प्रयाजन के लिए भारतीय खान ब्यूरो के खान महा-निर्देशक और प्रादेशिक खान निर्देशक को सक्षम प्राधिकारी समझा जाएगा।”

9 नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अतः स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“23क. ऐसे व्यक्तियों को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं हैं खनन पट्टा मंजूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना—केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है किसी खनन की बाबत कोई पट्टा मंजूर या नवीकृत नहीं किया जाएगा।”

10. नियम 24 के उपनियम (2) का लोप किया जाएगा।

11 नियम 24 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“24क. खनन पट्टे का नवीकरण।

- (1) खनन पट्टे के नवीकरण के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत में राज्य सरकार, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की मार्फत जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे उस तारीख से पूर्व जिसको पट्टा की अवधि का अवसान होने वाला है, किया जाएगा।
- (2) अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की बाबत मंजूर किए गए किसी खनन पट्टे के प्रथम नवीकरण के लिए कोई आवेदन, राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (2) के उपबंधों और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए मंजूर किया जा सकेगा।
- (3) ऐसे खनिज की बाबत जो अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, मंजूर किए गए किसी खनन पट्टे के प्रथम नवीकरण के लिए कोई आवेदन राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मंजूर किया जा सकेगा।
- (4) किसी खनन पट्टे के नवीकरण के लिए किसी आवेदन का निपटारा उसके प्राप्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, किया जायेगा।
- (5) यदि किसी आवेदन का निपटारा उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो उसे इंकार कर दिया गया समझा जाएगा।
- (6) यदि राज्य सरकार द्वारा पट्टे के अवसान की तारीख से पूर्व उपनियम (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर समय किसी खनन पट्टे के प्रथम नवीकरण के लिए किए गए किसी आवेदन का निपटारा नहीं किया गया है, तो उस पट्टे की अवधि, राज्य सरकार के उस पर आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की और अवधि तक या उसकी समाप्ति तक जो भी कम हो, बढ़ाई गई गमझी जाएगी।
- (7) किसी खनिज की बाबत खनन पट्टे का द्वितीय या पश्चात्कर्ती नवीकरण, राज्य सरकार द्वारा केवल केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और धारा 8 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मंजूर किया जाएगा।

24ख ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में खतन पट्टे का नवीकरण जो स्वयं अपने उद्योग में खनिज का उपयोग कर रहा है—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे खनिज के लिए, जिसका उपयोग उसके स्वयं के उद्योग में होता है, खतन पट्टा धारण कर रहा है दस वर्ष की अवधि के लिए अपने खतन पट्टे के नवीकरण के लिए हकदार होगा जब तक कि वह उसके कम अवधि के लिए आवेदन नहीं करता है।

स्पष्टीकरण —“अपना उद्योग” से ऐसा कोई उद्योग अभिप्रेत है, जिसका पट्टेदार स्वामी है या जिसमें वह पचास प्रतिशत से अधिक नियंत्रण हिस्से रखता है।”

12. नियम 26 के उपनियम (1) में, “राज्य सरकार शब्दों व पश्चात्” “सुनवाई का कोई अवसर दिए जाने के पश्चात् और” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

13. नियम 27 में—

(1) उपनियम (1) के खंड (ग) में,
“अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर जैसी कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत की जाए” अनुसूची में विनिर्दिष्ट बंदों पर शब्द रखे जाएंगे,

(11) उपनियम (1) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात् —

“(ग) पट्टेदार, समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन विहित, न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का सदाय नहीं करेगा,

(ब) पट्टेदार खान अधिनियम, 1952 के उपबन्धों का पालन करेगा,

(घ) पट्टेदार उसी क्षेत्र या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा चुने गए किसी अन्य क्षेत्र में किसी पूर्वोक्त सफाई के कारण नष्ट हुए वृक्षों की संख्या के दो गुने से अधिक वृक्ष या उम्र के वृक्षों तक, जो मर जायें हों, वृक्षारोपण, ऐसे सफाई के कारण नष्ट हुए पुष्कर-स्पतियों के पुनः वृक्षारोपण के उपाय करेगा।

(न) पट्टेदार, भूमि की सतह के अधिभागों का उलने प्रतिफल का सदाय करेगा, जितना इन नियमों के अधीन संवेद्य हो,

(प) पट्टेदार, धारा 18 के अधीन विरहित खनिज संरक्षण और विकास नियमों का अनुपालन करेगा।”

14. नियम 28 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् —

“28 पट्टे का व्ययगत होना।

(1) इन नियमों की अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए जहाँ पट्टे के निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर खतन सफाई प्रारंभ नहीं की गई है, या ऐसी सफाई प्रारंभ के पश्चात् एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए बंद कर दी गई है तो राज्य सरकार, आवेदन द्वारा खतन पट्टे को व्ययगत घोषित कर देगी और पट्टेदार को इस घोषणा को ससूचित करेगी।

(2) जहाँ पट्टेदार, पट्टे के निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर खतन सफाई प्रारंभ करने में असमर्थ रहता है या अपने नियंत्रण से परे कारणों से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए खतन सफाई बंद रखता है, वहाँ वह ऐसी अवधि के अवसान के कम से कम तीन मास पूर्व, उसके कारणों को स्पष्ट करते हुए, राज्य सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा,

(3) उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ 200 रु की फीस संलग्न की जाएगी,

(4) राज्य सरकार, उपनियम (2) के अधीन किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति पर और खतन सफाईओं का प्रारंभ करने या उसके बंद करने के कारणों की पर्याप्तता और वास्तविकता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर, उस तारीख से पूर्व जिसका पट्टा अन्यथा व्ययगत था, पट्टे की अवधि का बढ़ाने या बढ़ाने से इंकार करने का कोई अधिकार पारित कर सकेगी

परन्तु, जहाँ राज्य सरकार उपनियम (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, उस तारीख के अवसान से पूर्व जिसका पट्टा अन्यथा व्ययगत था गया हो, कोई अधिकार पारित नहीं करती है, वहाँ पट्टे की अवधि राज्य सरकार द्वारा आवेदन किए जाने तक या एक वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो, बढ़ाई गई समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण — जहाँ खतन पट्टे के निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर खतन सफाईओं का प्रारंभ —

(क) सही अधिकारों के अधिनियम या

(ख) पट्टा क्षेत्र का कब्जा लेने, या

(ग) मशीनरी के प्रवास या प्रतिष्ठापन, या

(घ) बैंकों या किसी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में बाधा होने के कारण और पट्टेदार न्यूनतम रूप से किसी शपथ ग्रहण शपथ-पत्र द्वारा समर्थित दस्तावेजों माध्यम प्रस्तुत करने में समर्थ है, वहाँ यदि सफाई के प्रारंभ की जाते के लिए पर्याप्त कारण है और/या वह पट्टेदार के नियंत्रण में परे है तो राज्य सरकार विचार कर सकेगी।

15. नियम 59 के उपनियम (1) के खंड (ठ) में “सरकार द्वारा आरक्षित” शब्दों के स्थान पर “राज्य सरकार द्वारा आरक्षित” शब्द रखे जाएंगे।

16. नियम 71 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय और नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् —

अध्याय X

72 मरुत के अधिकारों और के स्वामी का प्रतिफल का सदाय —

(1) पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति या खतन पट्टे का धारक, उस भूमि की सतह के अधिभागों को, जिस पर वह, यथास्थिति पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति या खतन पट्टा धारण करता है, उसने वार्षिक प्रतिफल का सदाय करने का दावा होगा जितना राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निम्न नियुक्त किसी अधिकारों द्वारा उपनियम (2) से (4) में उपबोधित रीति से अधिभागित किया जाए।

(2) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि से भिन्न कृषि भूमि का दशा में वार्षिक प्रतिफल की रकम की गणना पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए समस्त भूमि से खेती से प्राप्त औसत वार्षिक शुद्ध आय के आधार पर की जाएगी।

(3) गैर कृषि भूमि का दशा में वार्षिक प्रतिफल की रकम की गणना पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए समस्त भूमि में औसत वार्षिक भाटक मूल्य के आधार पर की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक प्रतिफल का प्रतिफल या उससे पहले या राज्य सरकार द्वारा इस निम्न निर्दिष्ट रीति से, संवेद्य होगा।

73. नुकसान के लिए प्रतिकर का निर्धारण :—

- (1) किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार भूमि में पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं द्वारा हुए नुकसान का यदि कोई हो निर्धारण करेगी और, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा भूमि सतह के अधिभागी को सदैव प्रतिकर को स्वयं अवधारित करेगी।
- (2) ऐसा प्रत्येक निर्धारण पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के समाप्त किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा इस निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उसका क्रियाव्ययन किया जाएगा।

74. जहां भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आदि द्वारा पूर्वेक्षण संक्रियाएं की जाती हैं वहां अधिसूचना का किया जाना।

- (1) जहां, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के अणु ऊर्जा विभाग के अणु खनिज प्रभाग, राज्य सरकार के भूतन्त्र एवं खनिजकर्म निदेशालयों (जहाँ वे किसी भी नाम से जानें हों) या खनिज गवेषण निगम लिमिटेड द्वारा पूर्वेक्षण संक्रियाएं की जाती हैं, वहां राज्य सरकार, उस क्षेत्र और उस अवधि का भोग देने हुए जिसके लिए पूर्वेक्षण संक्रियाएं की जाती हैं, राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी।
- (2) राज्य सरकार, किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऐसे क्षेत्र या उनमें किसी भाग के लिए जिसके लिए उपनियम (i) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर नहीं करेगी।
- (3) राज्य सरकार उपनियम (i) के अधीन जारी की गई अधिसूचना को प्रतिसूचित कर सकती है, यदि अधिसूचना में कथित अवधि से पहले पूर्वेक्षण संक्रियाएं पूरी कर ली गई हों।

75. राज्य सरकार द्वारा पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं :—

- (1) जहां कोई राज्य सरकार, किसी खनिज की पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं के लिए प्रस्थाना करती है, वहां वह राजपत्र में ऐसे क्षेत्र का भोग देते हुए और ऐसी अवधि जिसके भीतर ऐसी संक्रियाएं करने की प्रस्थापना की गई है, अधिसूचना जारी करेगी।
- (2) जहां किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार के साथ किसी संधि या उपसंधि के आधार पर या किसी अन्य आधार पर कोई पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं की जाती हैं, वहां प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, इन नियमों के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार समझा जाएगा और वह तदनुसार इसके सभी उपबंधों और खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1958 के उपबंधों के अधीन होगा।

17. अनुसूची 1 में,—

(1) प्ररूप क, क-1 और क-2 का लागू किया जाएगा।

(2) प्ररूप ख के पैरा 3 में,—

(क) खंड (V) और (VI) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (X) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतर्भावित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(Xक) (क) क्या आवेदक, उस क्षेत्र पर, जिसके लिए वह पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अपेक्षा करता है, सतही अधिकार रखता है? !

(ख) यदि नहीं, तो क्या उसने पूर्वेक्षण संक्रियाओं के लिए भूमि के स्वामी और अधिभागी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि ऐसा है तो स्वामी और अधिभागी से प्राप्त की गई लिखित सहमति फाइल की जाए”।

(ग) खंड (Xii) के स्थान के निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् :—

“(Xiii) ऐसे शपथपत्र के साथ जिसमें यह वर्णित हो कि आवेदक अधिनियम, 1961 के अधीन यथावहित आवेदक की अद्यतन विवरणियां फाइल कर दी गई हैं और संदेय कर का संदेय जिसके अंतर्गत स्वयं निर्धारण कर भी सम्मिलित है, कर दिया गया है।”

(घ) खंड (xi) में,—

“राज्य सरकार की अधिकारिता के भीतर” शब्दों के स्थान पर “प्रत्येक राज्य में किसी शपथपत्र द्वारा सम्पन्न रूप से सम्पन्न” शब्द रखे जाएंगे।

(iii) प्ररूप ग का लोप किया जाएगा।

(vi) प्ररूप ड के पैरा 2 में,—

(क) खंड (v) और (vi) का लोप किया जाएगा,

(ख) खंड (vii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(vii) ऐसे शपथपत्र के साथ जिसमें यह वर्णित हो कि आवेदक अधिनियम, 1961 के अधीन यथावहित आवेदक की अद्यतन विवरणियां फाइल कर दी गई हैं और संदेय कर का संदेय जिसके अंतर्गत स्वयं निर्धारण कर भी सम्मिलित है, कर दिया गया है।”

(ग) खंड (Xii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतर्भावित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(Xiiक) (क) क्या आवेदक, उस भूमि क्षेत्र पर, जिसके लिए वह पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण की अपेक्षा करता है, सतही अधिकार बनाए रखे हुए है?

यदि नहीं तो, क्या उसने सर्वेक्षण संक्रियाओं के लिए स्वामी और अधिभागी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि ऐसा है तो भूमि के स्वामी और अधिभागी से प्राप्त की गई लिखित सहमति फाइल की जाए।

(Xiiख) प्रत्येक राज्य में, खनिजवार क्षेत्रों की विभिन्नता दर्शाते हुए कोई ऐसा शपथपत्र जिसे आवेदक या उसका साथ संयुक्त रूप से कोई व्यक्ति—

(i) किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन पहले से हो धारण कर रहा है,

(ii) उसके लिए आवेदन किया है किन्तु मंजूर नहीं किया गया है; और

(iii) उसके लिए साथ-साथ आवेदन किया है।”

(v) प्ररूप च में—

(क) भाग II में, पैरा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतर्भावित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(4क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का संशय नहीं करेगा,

(4ख) खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

(ग) अपने खर्च पर पर्यावरण के संरक्षण के उपाय जैसे कि वृक्षारोपण खनन की गई भूमि का पुनरुद्धार पर्यावरण नियंत्रण युक्तियों का उपयोग और ऐसे अन्य उपाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बिहित किए जाएं।

(घ) भूमि के सतह के अधिभोगी को, इन नियमों में अधि-कथित तारीख और रीति में प्रतिकर का संशय करेगा;"

(ख) भाग-IV के पैरा (3) में, "पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का कोई भंग नहीं किया गया और" शब्दों के पश्चात् "ऐसी भूमि में खनिज संसाधनों की स्थापना करने के लिए पूर्वक्षण संक्रियाएं की गई हैं" शब्द प्र-स्थापित किए जाएंगे।

(ग) पैरा 3(क) में, "जो उस अवधि की प्राप्ति होगी। जिसके लिए अनुज्ञप्ति मूलतः अनुवन्त की गई है" शब्दों

के स्थान पर "अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए विहित अवधि में या उस अवधि में जिसके लिए आवेदन किया गया है, जो भी कम हो, से अनधिक के लिए" शब्द रखे जाएंगे।

(vi) प्ररूप ज में, नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित मंत्र अंतर्स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"7क अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रत्येक राज्य में उस क्षेत्र और खनिजों के खोरे, जिनके लिए आवेदक, पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति रखता है,"

(vii) प्ररूप शुरु के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा अर्थात् :—

"प्ररूप शुरु"

(तीन प्रतियां में प्रस्तुत किया जाए)

.....
मे
(तारीख) को प्राप्त हुआ प्राप्त करने वाले
अधिकारी के आदेशाक्षर

.....सरकार खनन पट्टे के लिए आवेदन [खनिज रियायत नियम, 1960 का
नियम 22(1) देखें]
तारीख 19
मेवा मे,
.....

मार्फत :

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे / हमें खनिज रियायत नियम, 1960 के अधीन खनन पट्टा मंजूर किया जाएगा।

2. इस आवेदन की बाबत क्रमशः 500 रु. और 1000 रु. की राशि जो उक्त नियम के नियम 22 के उपनियम (3) के अधीन प्रारम्भिक व्ययों के बारे में संदेय फीस है, (स्टेट बैंक आफ इंडिया/खजाने की चालान रसीद म तारीख द्वारा जमा कर दी गई है।

3. अपेक्षित विनिर्दिष्टियां नीचे दी गई हैं :—

- (1) आवेदक का नाम पूरे पते सहित
आवेदक की प्रास्थिति—
- (2) क्या आवेदक कोई प्राइवेट व्यष्टि/सहकारी/फर्म/संगम/प्राइवेट कंपनी/लोक कंपनी/
पब्लिक सेक्टर उपक्रम/संयुक्त सेक्टर उपक्रम या कोई अन्य है।
- (3) यदि आवेदक,—
 - (क) व्यष्टि हो, तो उसकी राष्ट्रिकता, अर्हताएं और खनन के संबंध में उसका अनुभव।
 - (ख) कोई प्राइवेट कंपनी हो तो,—
मनी मन्त्रालय/बोर्ड के निर्देशकों की राष्ट्रिकता के साथ जो रजिस्ट्रारकरण का स्थान और निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति।
 - (ग) कोई लोक कंपनी हो तो उसके निर्देशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धारित शेयर पट्टी की प्रतिगणना और उसके साथ निगमन का स्थान और निगम प्रमाणपत्र की प्रति।

- (ग) फर्म या संगम हो, जो फर्म के सभी भागीदारों या संगम के सदस्यों की राष्ट्रिकता :
- (ङ) यदि सहकारिता हो तो, गैर भारतीय सदस्यों यदि कोई हों की राष्ट्रिकता और उसके साथ रजिस्ट्रीकरण का स्थान तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति

(4) आवेदक की वस्ति या कारबार की प्रकृति

(5) मतभेद दस्तावेजों की विशिष्टियाँ—

दस्तावेज	निर्देश
(क) खनन संबंधी शोध समशीोधन प्रमाणपत्र	गा
(ख) खनन संबंधी शोध समशीोधन, समशीोधन प्रमाणपत्र के बदले शोधपत्र इस शर्त के अधीन रहने हुए कि आवेदन किए जाने के नब्बे दिन की अवधि के भीतर खनन पट्टे में संबंधित शोध समशीोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।	या
(ग) शोधपत्र, जब कोई खनन पट्टा धारण न कर रहा हो।	
(घ) इस अध्याय का शोधपत्र कि आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन यथोचित अखतन आयकर विवरणियाँ फाइल कर दी हैं और सदेव कर का, जिसके अन्तर्गत स्वयं निर्धारण कर भी सम्मिलित है, सदाय भर दिया गया है।	
(6) खनिज जिसका/जिनका खनन करने का आवेदक का आशय है	
(7) वह अधि अधिक जिसके लिए खनन पट्टा अपेक्षित है	
(8) उस क्षेत्र का विस्तार जिसके लिए खनन पट्टा अपेक्षित है	
(9) उस क्षेत्र के स्थीरे जिसके बारे में खनन पट्टा अपेक्षित है	

जिला तालुका ग्राम खमरा म प्लाट न क्षेत्र स्वामित्व/अधिभाग

- (10) क्षेत्र का मश्रिप्त वणन निम्नलिखित के प्रति विशेष रूप से निर्देश हो
- (क) क्या आवेदक, उस क्षेत्र पर, जिसके लिए वह कोई खनन अनुज्ञप्ति को मजूरी के लिए आवेदन कर रहा है, सन्तुष्ट अधिकार रखता है।
- (ख) यदि नहीं तो, क्या उसने खनन सत्रियोंओं के लिए भूमि के स्वामी और अधिभागों की सहमति प्राप्त कर ली है, यदि ऐसा है तो स्वामी और अधिभागों की लिखित रूप से सहमति प्राप्त की जाए और फाइल की जाए।
- (11) (क) सरिताओं का या ओघों जैसे प्राकृतिक लक्षणों के संबंध में क्षेत्र की स्थिति।
- (ख) ग्राम क्षेत्र की दशा में, ग्राम का नाम खमरा म, प्रत्येक क्षेत्त या उसका भाग का, जिसके लिए आवेदन किया गया है डेक्टर क्षेत्र।
- (ग) ऐसे क्षेत्र की दशा में जिसके लिए आवेदन किया गया है वन क्षेत्र के अधीन आता हो, तो निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी जाएँ—
- (1) वन प्रभाग, स्पाक और रेन्ज
 - (2) वन की विधिक प्राप्ति (अर्थात् आरक्षण, संरक्षण अवर्धित आदि)
 - (3) क्या वह राष्ट्रीय उद्यान या वन्यप्राणी अभयारण्य का भाग है
 - (4) क्षेत्र में वनस्पति की किस्म और उसका विस्तार
 - (5) ऐसे क्षेत्रों में लिए जहाँ कोई वन मानचित्र या भूकर मानचित्र उपलब्ध नहीं है ऐसे पैमाने पर एक स्केच रेखांक प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें आवेदक क्षेत्र और यदि आवेदन क्षेत्र का किसी अन्य विद्यमान पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के क्षेत्रों की सीमाओं के साथ कोई सामान्य बिन्दु या रेखा हो तो उस विद्यमान खनन पट्टे या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति क्षेत्र की सीमा यदि कोई हो, दर्शाते हैं।

(12) आशेषित क्षेत्र रेखाओं पर नीचे बताए गए अनगार चिह्नित किया जाना चाहिए।

- (क) यदि क्षेत्र का कोई भूकर मानचित्र उपलब्ध है तो इस मानचित्र पर ग्राम का नाम, खसरा, संख्याक, प्रत्येक क्षेत्र (फोन्ड) और उसके भाग का क्षेत्रफल हेक्टर में दर्शित करते हुए वह क्षेत्र चिह्नित किया जाना चाहिए।
- (ख) वन मानचित्रों की दशा में मानचित्र पर रेखा तथा पतन श्रेणियां दर्शित करने हुए क्षेत्र चिह्नित किया जाना चाहिए।
- (ग) यदि भूकर मानचित्र और वन मानचित्र दोनों ही उपलब्ध नहीं हैं तो वह क्षेत्र ऐसे पैमाने पर बनाए गए एक रेखांक पर चिह्नित किया जाना चाहिए जिसमें कि इस रेखांक में सभी महत्वपूर्ण सतही तथा प्राकृतिक लक्षण, उन रेखाओं की लम्बाई चौड़ाई जिनसे क्षेत्र की सीमा बनती है और किसी महत्वपूर्ण प्रमुख तथा निश्चित बिन्दु या बिन्दुओं से सभी कोण बिन्दुओं से विक्रमान तथा दूरी दर्शित होती हो।

(13) प्रत्येक राज्य में एक मध्यमतर द्वारा समर्पित उन क्षेत्रों की उन खनिजों के अनुसार विनिर्दिष्टियां :—

- (क) जिनके लिए आवेदक या उसके साथ संयुक्त हित रखने वाला कोई व्यक्ति पहले ही खनन पट्टे के अधीन उन्हें धारण करना है।
- (ख) जिनके लिए आवेदक या उसके साथ संयुक्त हित रखने वाला कोई व्यक्ति आवेदन कर चुका है किन्तु वह मंजूर नहीं हुआ है, या
- (ग) जिनके लिए आवेदक या उसके साथ संयुक्त हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा एक साथ आवेदन किया जा रहा है।

(14) यदि कोई संयुक्त हित हो तो उसकी प्रकृति।

(15) (क) क्या आवेदक ऊपर (10) में वर्णित क्षेत्र की बाबत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारण करने है? यदि धारण करता हो तो उसका संख्याक और उसकी मसूरी की तारीख तथा वह तारीख जिस तारीख को उसका अवमान होने वाला है दीजिए।

(ख) क्या आवेदक ने पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन धारित क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रियाएं की हैं और राज्य सरकार को अनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 16 द्वारा यथा अपेक्षित, अपनी रिपोर्ट भेज दी है? यदि नहीं तो ऐसा न करने के कारण बताइए।

(16) खनिज/अयस्क निकाय/निकायों का विस्तृत प्राचल।

- (क) खोदाई की लंबाई, औसत चौड़ाई और गहराई।
- (ख) चट्टान भित्ति और फूट/भित्ति पार्श्व।
- (ग) क्या क्षेत्र भूवैज्ञानिक रूप से बड़े पैमाने पर अध्ययनगुण है या तुलनात्मक दृष्टि से भूवैज्ञानिक अध्ययनों से मुक्त है। (क्षेत्र के भूवैज्ञानिक मानचित्र की प्रति संलग्न की जाए)
- (घ) श्रेणी (श्रेणियों) सहित निर्धारित आरक्षित (स्रोतक नमूनों के रसायनिक विश्लेषण रिपोर्टें संलग्न की जाए)
- (ङ) क्या क्षेत्र अक्रांटपूर्व है, यदि नहीं तो वह विस्तार जिस तक इसमें पहले ही कार्य किया जा चुका है। पुराने कार्य की दशा में, क्षेत्र के भूवैज्ञानिक मानचित्र पर उनकी अवस्थितियां दर्शित की जाए

(17) खान का विस्तृत प्राचल।

- (क) खनन संक्रियाओं के प्रारंभ की प्रस्तावित तारीख
- (ख) प्रथम पाँच वर्षों के दौरान खनिज उत्पादन की प्रस्तावित दर (वर्षवार)।
- (ग) उत्पादन की प्रस्तावित दर, जस खान पूर्णरूप से विकसित हो।
- (घ) खान की पूर्वानुमानित क्षमता।
- (ङ) खनन की प्रस्तावित प्रणाली
(भूमिगत या विस्तृत)
(i) यदि भूमिगत हो तो, निक्षेप खनिज/अयस्क तक पहुंचने की प्रणाली, चाहे वह धारण है या कूपक के माध्यम में हो।

(ii) यदि विदित हो तो :

अयस्क अनुपात और संपूर्ण खड़े हाल में प्रतिभार ।

(घ) प्रतिभार/अपशिष्ट और कूड़े करकट को फेंकने के लिए चुनी गई भूमि की प्रकृति (भूमि का प्रकार क्या है, क्या वह कृषि योग्य चारागाह, अनुर्वरक, लवणीय आदि प्रकार की भूमि है) प्रस्तावित स्थल खान संकर्म रेखांक में दर्शाया गया है । अपशिष्ट और कूड़े करकट को फेंकने के लिए पृथक रखे गए क्षेत्र का विस्तार भी हैक्टर में दें ।

(18) केन्द्रीय सरकार द्वारा समझू रूप से अनुमोदित खनन रेखांक ।

(19) वन रीति जिसमें निकाले गए खनिज का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाए :

(क) (i) यदि परिशोधन उपयोग के लिए है तो संयंत्र की अवस्थिति और उद्योग :

(ii) भारत में खपत के लिए विश्व के लिए :

(ख) यदि विदेश में निर्यात के लिए है, तो, उपदर्शित करें—

(i) उन देशों के नाम जिनके लिए उसका निर्यात किया जाना संभाव्य है, जहां खान की स्थापना 100% निर्यातानुमुख या प्रतिबंधित आधार पर की जा रही है ।

(ii) क्या खनिजों को कच्चे रूप में या संसाधन के पश्चात् निर्यात किया जाएगा । संसाधन के प्रक्रमों को भी उपदर्शित करें, क्या अंतिम उत्पाद मध्यवर्ती या अंतिम प्रक्रम पर है ।

(ग) यदि इसका उपयोग देश के भीतर किया जाना है तो,—

(1) उन उद्योग/उद्योगों को उपदर्शित करें जिनमें इसका उपयोग किया जाएगा ।

(2) क्या इसका कच्चे रूप में या (कुचलकर/पीसकर/संजोकरण/निष्चूरण संसाधन के पश्चात् प्रदाय किया जाएगा ।

(3) क्या इसे उद्योग करने की आवश्यकता होगी और यदि ऐसा है, तो क्या परिष्करण संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है । ऐसे संयंत्र की क्षमता और वह अवधि जिस तक इसकी स्थापना हो जाएगी, उपदर्शित करें ।

(घ) कोयला या अन्य प्रयुज खनिजों/अयस्कों की वशा में, उपलब्ध विद्यमान रेल पत्थरहन सुविधा और यदि कोई, अतिरिक्त परिवहन सुविधा अपेक्षित हो तो, उमरे: व्योरे ।

(20) खान के पर्यवेक्षण के लिए उपलब्ध तकनीकी कार्मिक का नाम, अहंताएं और अनुभव ।

(21) (i) आदेशक के विस्तीय साधन :

(ii) खान संनिर्माण के दौरान पूर्वानुमानित वार्षिक वित्तीय विनिधान और वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के प्रथम तक कुल विनिधान ।

(22) (क) अपशिष्ट जल की प्रकृति (उदाहरणार्थ क्या घम्लीय है) यदि ऐसा है तो उसका प्राशयित पी.एच. मू:य .

(ख) आदेशन पत्र के साथ खनन स्कीम के प्रमुख लक्षणों का विवरण संलग्न होता चाहिए । यह माशारणतया खनन महायता रिपोर्ट में दी गई "परि-योजना एक दृष्टि में" के आशार पर जिसके अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित नक्षण भी है, होनी चाहिए ।

मै/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि उपर दी गई विनिष्टियां सही हैं और मै/हम ऐसे कोई भी अन्य व्योरे जिनकी आप अपेक्षा करें जिनके अंतर्गत शुद्ध रेखांक तथा प्रतिभूति विशेष आदि आने हैं देने के लिए तैयार हूं/हैं ।

भवदीय,

आदेशक के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

1587 GI/86—2

1 “= 1 मील के मापमान का स्थल रूपरेखीय मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण, हाथी बरखला, देहरादून, के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

यदि आयेदित खनिज अनुसूचित खनिज है तो मूल आयेदन के साथ तीन प्रतियों में विस्तृत रेखांक और स्थल रूपरेखीय मानचित्र संलग्न करना होगा।

टिप्पणी :—1 यदि आयेदन पर आयेदक के किसी प्राधिकृत अधिकारी ने हस्ताक्षर किए हों तो मुन्तारनामा संलग्न किया जाना चाहिए।

2 तब के सिवाय जबकि खनन पट्टे का आयेदन ऐसे क्षेत्र के लिए हो, जो, आयेदक द्वारा पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति के अधीन पहले से ही धारित हो, आयेदन केवल एक संयुक्त क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए।

3 क्षेत्र के उचित सीमांकन के लिए, विशेष रूप से जब आयेदित क्षेत्र 40 हेक्टर या कम हो, ऐसे बड़े आकार का मानचित्र, जो उपलब्ध हो सके, संलग्न किया जाना चाहिए।”

(8) प्ररूप-अ के पैरा 2 में—

(क) खंड (5) और (6) का लोप किया जाएगा।

(ख) खंड (7) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(7) ऐसे शपथपत्र के साथ जिसमें यह वर्णित हो कि आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन यथा विहित आयकर की भ्रष्टान्त विवरणियां फाइल कर दी गई हैं और सदेय कर का संदाय, जिसके अंतर्गत स्वयं निर्धारण कर भी सम्मिलित है, कर दिया गया है।”;

(ग) खंड (10) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(10क) (क) क्या आयेदक, उस भूमि क्षेत्र पर जिसके लिए वह पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति के नवीकरण की अपेक्षा करता है, सही अधिकार बनाए रखे हुए है ?

(ख) यदि नहीं तो क्या उसने सर्वेक्षण सक्रियताओं के लिए स्वामी और अधिभोगी की सहमति प्राप्त कर ली है। यदि ऐसा है तो भूमि के स्वामी और अधिभोगी से प्राप्त की गई लिखित सहमति फाइल की जाए।

(10ख) प्रत्येक राज्य में, खनिजवार क्षेत्रों की विशिष्टता दर्शित करने हुए कोई ऐसा शपथपत्र जिसे आयेदक या उसके साथ संयुक्त रूप से कोई व्यक्ति—

(1) किसी पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति के अधीन पहले से ही धारण कर रहा है,

(2) उसके लिए आयेदन किया है किन्तु मंजूर नहीं किया गया है; और

(3) उसके लिए साथ-साथ आयेदन किया है।

(10ग) खनन रेखांक में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) खनिज निकाय का विस्तार उस स्थान या उस स्थलों को जहां प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाना है और उसके विस्तार को दर्शित करने हुए क्षेत्र का रेखांक, विस्तृत वर्ग गज आंकड़ों और आयेदक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इकट्ठे किए गए पूर्वोक्त आंकड़ों के आधार पर उत्खनन के स्थल (स्थलों) के विस्तृत

रेखांक; पट्टे के प्रथम पांच वर्षों के लिए खनन की कोई अनन्तित स्कीम;

(ख) क्षेत्र की खनिज धारकतियों सहित भूविज्ञान और आग्निशी के व्योरे;

(ग) वर्ष दर वर्ष उत्खनन के लिए वार्षिक कार्यक्रम; और

(घ) प्राकृतिक जलमार्ग, वन क्षेत्र और वृक्षों की सघनता यदि कोई हो, वनों में खनन क्रियाओं के समाधान, भूमि सतह और वायु तथा जलाशय सहित पर्यावरण, दूषित करने वाले क्षेत्र का रेखांक, वृक्षारोपण भूमि पुनरुद्धार, द्वारा क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए स्कीम के व्योरे पर्यावरण नियंत्रण युक्तियों का उपयोग;”

(9) प्ररूप ट में, भाग 7 में खंड 11 के पश्चात् निम्नलिखित खंड संतर्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“11क. पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का संवाय नहीं करेगा;

11ख. पट्टेदार, खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों का पालन करेगा;

11ग. पट्टेदार, पर्यावरण की सुरक्षा के उपाय जैसे वृक्षारोपण भूमि का पुनरुद्धार पर्यावरण नियंत्रण युक्तियों के उपाय और अपने खर्च पर ऐसे अन्य उपाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएंगे।

11घ. पट्टेदार, भूमि के अधिभोगी को, उन नियमों में अधिकृतित तारीख और रीति से प्रतिकर का संदाय करेगा।

(10) प्ररूप ट में, खंड 4 का लोप किया जाएगा।

पाद टिप्पण . —मूल नियमों का पहले भी संशोधन किया गया था। ऐसे संशोधनों की सूची संलग्न है।

[फा.सं. 7/1/86-एम VI]

सूची

- 1 अधिसूचना सं. 1/34/71-एम-6 तारीख 21-5-73
- 2 अधिसूचना सं. एम-II-152/62 तारीख 22-7-63
- 3 अधिसूचना सं. 1/34/63-एम-II तारीख 23-5-70
- 4 अधिसूचना सं. 1/26/71-एम II तारीख 14-2-72
- 5 अधिसूचना सं. 1/2/63-एम II तारीख 23-2-68
- 6 अधिसूचना सं. 1/3/68-एम II तारीख 30-3-68
- 7 अधिसूचना सं. एम II-109/14/61 तारीख 7-9-61
- 8 अधिसूचना सं. 1/22/63-एम II तारीख 18-7-63
- 9 अधिसूचना सं. 1/24/75-एम II तारीख 2-5-79
- 10 अधिसूचना सं. 1/3/63-एम VI तारीख 17-1-69
- 11 अधिसूचना सं. 1/33/67-एम VI तारीख II तारीख 22-7-71
- 12 अधिसूचना सं. एम II-160/11/61 तारीख 6-5-63
- 13 अधिसूचना सं. 1/3/71-एम VI तारीख 6-9-71
- 14 अधिसूचना सं. 1/51/65-एम II तारीख 26-2-69
- 15 अधिसूचना सं. एम II-162/II/62-तारीख 16-1-80
- 16 अधिसूचना सं. 3/51/75-एम II तारीख 16-1-80
- 17 अधिसूचना सं. एम II-152/58/61 तारीख 30-4-63
- 18 अधिसूचना सं. एम II-153/33/60 तारीख 24-9-63
- 19 अधिसूचना सं. 1/26/66-एम VI तारीख 4-3-67
- 20 अधिसूचना सं. 7(4)/85-एम VI तारीख 22-9-86.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 10th February, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 86(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Mineral (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960,—

(1) Rules 4, 4A, 5, 6, 7 and 7A shall be omitted.

(2) In rule 9, in sub-rule (2)—

- (i) clauses (b) and c) shall be omitted;
- (ii) after clause (d) but before the first proviso, the following clauses shall be inserted, namely :—

“(e) an affidavit stating that the applicant has—

- (i) filed up-to-date income tax returns;
- (ii) paid the income tax assessed on him; and
- (iii) paid the income tax on the basis of self-assessment as provided in the Income Tax Act, 1961;

(f) an affidavit showing particulars of areas mineral-wise in each State, which the applicant or any person jointly with him—

- (i) already holds under a prospecting licence;
- (ii) has applied for but not granted; and
- (iii) being applied for simultaneously.

(g) a statement in writing that the applicant has, where the land is not owned by him, obtained surface rights over the area or has obtained the consent of the owner for starting prospecting operations. Provided that no such statement shall be necessary where the land is owned by the Government.”

(iii) in the first proviso, after the words “mining dues” the words “or income tax” shall be inserted.

3. After rule 10, the following rule shall be inserted, namely:—

“10A : Previous approval of the Central Government to be obtained by persons who are not Indian Nationals. No prospecting licence in respect of any mineral shall be granted to or renewed in favour of a person, who is

not an Indian National, except with the previous approval of the Central Government.”

4. In rule 11, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :—

(2) (a) An application for the renewal of a prospecting licence shall be made at least ninety days before the expiry of the prospecting licence and shall be accompanied by—

- (i) a statement relating to the prospecting operations already undertaken by the applicant;
- (ii) the amount of expenditure incurred;
- (iii) the numbers of hours and days for which the work was undertaken; and
- (iv) the period which is required to complete the prospecting work.

(b) An application for the renewal of a prospecting licence shall be disposed of by the State Government before the expiry of the period of prospecting licence and if the application is not disposed of within that period, the licence shall be deemed to have been renewed for a period not exceeding the period prescribed for renewal of prospecting licence under sub-section (2) of section 7 of the Act, or the period for which an application is made, whichever is less.”

5. In sub-rule (1) of rule 12, after the words “the State Government may,” the words “after giving an opportunity of being heard and” shall be inserted.

6. In rule 14, in sub-rule (1), after clause (vii), but before the proviso the following clauses shall be inserted, namely :—

- (viii) the licensee shall not pay a wage less than the minimum wage prescribed by the Central or the State Government from time to time under the Minimum Wages Act, 1948;
- (ix) the licensee shall observe the provisions of the Mines Act, 1952;
- (x) the licensee shall take such measures for planting in the same area or any other area selected by the Central or the State Government not less than twice the number of trees destroyed by reason of any prospecting operations or to the extent possible, the restoration of flora and other vegetation destroyed by such operations as directed by the Central or the State Government from time to time at his own expense;
- (xi) the licensee shall pay to the occupier of surface of the land such compensation as may become payable under these rules;
- (xii) the licensee shall comply with the Mineral Conservation and Development Rules framed under section 18.”

7. In rule 22, in sub-rule (3) in clause (i).—(i) sub-clauses (b) and (c) shall be omitted; (ii) in sub-clause (d) before the first proviso, the following sub-clauses shall be inserted, namely :—

“(e) a mining plan duly approved by the Central Government. The mining plan shall incorporate :—

- (i) the plan of the area showing the extent of mineral body; spot or spots where the excavation is to be done in the first year and its extent; a detailed cross-section and detailed plan of spot (s) of excavation based on the prospecting data gathered by the applicant or any other person; a tentative scheme of mining for the first five years of the lease;
- (ii) details of the geology and lithology including mineral reserves of the area;
- (iii) the extent of manual mining or mining by use of machinery and mechanical devices;
- (iv) the plan of the area showing natural water courses, forest areas and density of trees if any, assessment of impact of mining activity on forest, land surface and environment including air and water pollution; details of scheme for restoration of the area by afforestation, land reclamation, use of pollution control devices and such other measures as may be directed by the Central or the State Government from time to time;
- (v) any other matter which the Central Government may require the applicant to provide in the mining plan;
- (f) an affidavit stating that the applicant has—
 - (i) filed up-to-date income tax returns;
 - (ii) paid the income tax assessed on him; and
 - (iii) paid the income tax on the basis of self-assessment as provided in the Income-Tax Act, 1961;
- (g) an affidavit showing particulars of area mineral-wise in each state, which the applicant or any person jointly with him.—
 - (i) already holds under a mining lease;
 - (ii) has already applied for but not granted;
 - (iii) being applied for simultaneously;
- (h) a statement in writing that the applicant has, where the land is not owned by him, obtained surface rights over the area or has obtained the consent of the owner for starting prospecting operations :

Provided that no such statement shall be necessary where the land is owned by the Government.

8. After rule 22, the following rules shall be inserted, namely :—

“22A Mining operations to be in accordance with Mining Plans :

- (1) Mining operations shall be undertaken in accordance with the mining plan duly approved by the Central Government.
- (2) A mining plan may be modified with the prior approval of the Central Government during the operation of a mining lease.

22B Mining plan to be prepared by recognised persons :—

- (1) No mining plan shall be approved by the Central Government unless it is prepared by a qualified person recognised in this behalf by the Central Government.
- (2) No person shall be recognised by the Central Government for purposes of sub-rule (1) unless he holds—

(i) a degree in mining engineering or a postgraduate degree in Geology granted by a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, including any institution recognised by the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 or any equivalent qualification granted by any University or institution outside India; and

(ii) experience of five years of working in a supervisory capacity in mining operations after obtaining the degree.

- (3) A person recognised to prepare a mining plan may also carry out modifications of an existing mining plan.

22C Grant of recognition by Central Government :

- (1) Any person possessing the qualifications and experience referred to in sub-rule (2) of rule 22B may apply for being recognised as a recognised person to the competent authority appointed for the purpose by the Central Government,
- (2) The competent authority, after making such enquiry as it deems fit, may grant or refuse to grant recognition and where recognition is refused, the competent authority shall record reasons in writing and communicate the same to the applicant
- (3) A recognition shall be granted for an initial period of two years and shall be renewable for the like period;

provided that the competent authority may refuse to renew recognition for reasons to be recorded in writing after giving

an opportunity of hearing to the person concerned.

- (4) An appeal shall lie to the Central Government against the order of the competent authority refusing to grant or renew an application for recognition.

Explanation : For the purpose of this rule, the Controller General and the Regional Controller of Mines of the Indian Bureau of Mines, shall be deemed to be competent authority."

9. After rule 23, the following rule shall be inserted, namely :—

"23A. Previous approval of the Central Government to be obtained for grant of mining lease to persons who are not Indian Nationals—No mining lease in respect of a mineral shall be granted to or renewed in favour of a person, who is not an Indian National except with the previous approval of the Central Government."

10. Sub-rule (2) of rule 24, shall be omitted.

11. After rule 24, the following rules shall be inserted, namely :—

"24A. Renewal of mining lease :—

- (1) An application for the renewal of a mining lease shall be made to the State Government in Form J, at least twelve months before the date on which the lease is due to expire, through such officer or authority as the State Government may specify in this behalf.
- (2) An application for the first renewal of a mining lease granted in respect of a mineral specified in the First Schedule to the Act, may, subject to the provisions of sub-section (2) of section 8, and with the previous approval of the Central Government, be granted by the State Government.
- (3) An application for the first renewal of a mining lease granted in respect of a mineral which is not specified in the First Schedule to the Act may, subject to the provisions of sub-section (2) of section 8, be granted by the State Government.
- (4) An application for the renewal of a mining lease shall be disposed of within a period of six months from the date of its receipt.
- (5) If an application is not disposed of within the period specified in sub-rule (4) it shall be deemed to have been refused.
- (6) If an application for first renewal of a mining lease made within the time referred to in sub-rule (1) is not disposed of by the State Government before the date of expiry of the lease, the period of that

lease shall be deemed to have been extended by a further period of one year or end with the date of receipt of the orders of the State Government thereon, whichever is shorter.

- (7) The second or subsequent renewal of a mining lease in respect of any mineral, shall be granted by the State Government only with the prior approval of the Central Government and be subject to the provisions of sub-section (3) of section 8.

B. Renewal of mining lease in favour of a person using the mineral in his own industry :—

Every person who is holding mining lease for a mineral which is used in his own industry shall be entitled for the renewal of his mining lease for a period of ten years unless he applies for a lesser period.

Explanation :—"Own industry" means an industry of which the lessee is the owner or in which he holds not less than fifty per cent of controlling interest."

12. In sub-rule (1) of rule 26, after the words "The State Government." the words "after giving an opportunity of being heard and" shall be inserted.

13. In rule 27—

- (i) in clause (c) of sub-rule (1), for the words "within the limits specified in Schedule IV as may be fixed from time to time by the State Government" the words "at the rates specified in the Third Schedule" shall be substituted;
- (ii) after clause (p) of sub-rule (1), the following clauses shall be added, namely :—
 - "(q) the lessee shall not pay a wage less than the minimum wage prescribed by the Central or State Government from time to time under the Minimum Wages Act, 1948;
 - (r) the lessee shall observe the provisions of Mines Act, 1952;
 - (s) the lessee shall take such measures for planting in the same area or any other area selected by the Central or State Government not less than twice the number of trees destroyed by reason of any mining operation or to the extent possible, the restoration of flora and other vegetation destroyed by such operations;
 - (t) the lessee shall pay to the occupier of the surface of the land such compensation as may become payable under these rules;
 - (u) the lessee shall comply with the Mineral Conservation and Development Rules framed under section 18."

14. For Rule 28, the following rule shall be substituted, namely :—

“28. Lapsing of leases :—

- (1) Subject to the other conditions of this rule where mining operations are not commenced within a period of one year from the date of execution of the lease, or is discontinued for a continuous period of one year after commencement of such operations, the State Government shall, by an order, declare the mining lease as lapsed and communicate the declaration to the lessee.
- (2) Where a lessee is unable to commence the mining operation within a period of one year from the date of execution of the mining lease, or discontinues mining operations for a period exceeding one year for reasons beyond his control, he may submit an application to the State Government, explaining the reasons for the same, at least three months before the expiry of such period;
- (3) Every application under sub-rule (2) shall be accompanied by a fee of Rs. 200/-;
- (4) The State Government may on receipt of an application made under sub-rule (2) and on being satisfied about the adequacy and genuineness of the reasons for the non-commencement of mining operations or discontinuance thereof, pass an order before the date on which the lease would have otherwise lapsed, extending or refusing to extend the period of the lease :

Provided that where the State Government on receipt of an application under sub-rule (2) does not pass an order before the expiry of the date on which the lease would have otherwise lapsed, the lease shall be deemed to have been extended until the order is passed by the State Government or until a period of one year, whichever is earlier.

Explanation :—Where the non-commencement of the mining operations within a period of the mining operations within a period of one year from the date of execution of minings lease is on account of delay in—

- (a) acquisition of surface rights; or
- (b) getting the possession of the leased area; or
- (c) supply or installation of machinery; or
- (d) getting financial assistance from banks, or any financing institutions;

and the lessee is able to furnish documentary evidence supported by a duly sworn affidavit, the State Government may consider if they are sufficient reasons and/or beyond the control of lessee for the non-commencement of operations.”

15. In sub-rule (1) of rule 59, in clause (e), for the words “reserved by Government” the words “reserved by the State Government” shall be substituted.

16. After rule 71, the following chapter and rules shall be added, namely :—

“CHAPTER—X

72. Payment of compensation to owner of surface rights etc. :—

- (1) The holder of a prospecting licence or mining lease shall be liable to pay to the occupier of the surface of the land over which he holds the prospecting licence or as the case may be, the mining lease, such annual compensation as may be determined by an officer appointed by the State Government by notification in this behalf in the manner provided in sub-rules (2) to (4).
- (2) In the case of agricultural land, other than land referred to in sub-rule (4), the amount of annual compensation shall be worked out on the basis of the average annual net income from the cultivation of similar land for the previous three years.
- (3) In the case of non-agricultural land, the amount of annual compensation shall be worked out on the basis of average annual letting value of similar land for the previous three years.
- (4) The annual compensation referred to in sub-rule (1) shall be payable on or before such date as may be specified by the State Government in this behalf.

73. Assessment of compensation for damage :—

- (1) After the termination of a prospecting licence or a mining lease, the State Government shall assess the damage, if any, done to the land by the prospecting or mining operations and shall determine the amount of compensation payable by the licensee or as the case may be, the lessee to the occupier of the surface land.
- (2) Every such assessment shall be made within a period of one year from the date of termination of the prospecting licence or mining lease and shall be carried out by an officer appointed by the State Government by notification in this behalf.

74. Issue of notification where prospecting operations are to be undertaken by the Geological Survey of India etc.

- (1) Where a prospecting operation is to be undertaken by the Geological Survey of India, the Indian Bureau of Mines, the Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy of the Central Government, the Directorate of Mining and Geology of any State Government (by

whatever name called), or the Mineral Exploration Corporation Limited, the State Government shall issue a notification in the Official Gazette giving details of the area, and the period for which prospecting operations are to be undertaken.

- (2) The State Government shall not grant any prospecting licence or mining lease to any other person for an area or a part thereof in relation to which a notification has been issued under sub-rule (1).
- (3) The State Government may revoke a notification issued under sub-rule (1), if the prospecting operations have been completed before the expiry of the period stated in the notification.

75. Prospecting or mining operation by State Governments :—

- (1) Where a State Government proposes to undertake prospecting or mining operations of any mineral, it shall issue a notification in the Official Gazette giving details of the area and the period for which such operations are proposed to be undertaken.
- (2) Where a prospecting or mining operations is undertaken by a person on the basis of a contract or sub-contract or on any other basis with the State Government, every such person shall be deemed to be a licensee, or as the case may be, a lessee for the purposes of these rules and shall accordingly be subject to all its provisions and the provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 1958."

17. In Schedule I,—

i) FORMS A, A-1 and A-2 shall be omitted.

(ii) in paragraph 3, of FORM B,—

- (a) clauses (v) and (vi) shall be omitted ;
- (b) after clause (x), the following clause shall be inserted, namely :—

"(xiiA) (a) Does the applicant have surface rights over the area for which he requires a prospecting licence ?

(b) If not, has he obtained the consent of the owner, and the occupier of the land for undertaking prospecting operations. If so, the consent of the owner and the occupier obtained in writing be filed."

- (c) for clause (xiii) the following clause shall be substituted, namely :—

"(xiii) An affidavit, that the up-to-date income-tax returns, as prescribed under the Income Tax Act, 1961, have been filed, and the tax due, including the tax on account of self assessment has been paid." ;

(d) in clause (xiv),

for the words, "within the jurisdiction of the State Governments", the words, "in each State duly supported by an affidavit", shall be substituted ;

(iii) FORM C shall be omitted ;

(iv) in paragraph 2, of FORM E,—

- (a) Clauses (v) and (vi) shall be omitted ;
- (b) for clause (vii) the following clause shall be substituted, namely :—

"(vii) An affidavit, that the up-to-date Income Tax returns, as prescribed under the Income Tax Act, 1961, have been filed and the tax due, including the tax on account of self-assessment has been paid." ;

- (c) After clause (vii), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(xiiA) (a) Does the applicant continue to have the surface rights over the areas of the land for which he requires renewal of the prospecting licence ?

(b) If not, has he obtained the consent of the owner and the occupier for undertaking prospecting operations ? If so, the consent of the owner and occupier of the land obtained in writing, be filed.

(xiiB) Particulars of the area mineralwise in each State only supported by an affidavit for which the applicant or any person jointly in interest with him—

(a) already holds under prospecting licence ;

(b) has already applied for but not granted ; or

(c) being applied for simultaneously."

(v) in FORM F,—

- (a) in PART II, after paragraph (9), the following paragraphs shall be inserted, namely :—

"(9A) To pay a wage not less than the minimum wage prescribed by the Central or State Government from time to time.

(9B) To comply with the provisions of the Mines Act, 1952.

(9C) To take measures, at his own expense, for the protection of environment like planting of trees, reclamation of mined land, use of pollution-control devices, and such other measures as may be prescribed by the Central or State Government from time to time.

(9D) To pay compensation to the occupier of the surface of the land on the date and in the manner laid down in these rules;"

(b) in Part IV, in paragraph (3), after the words, "conditions of the prospecting licence" the words, "has undertaken prospecting operations to establish mineral resources in such land" shall be inserted.

(c) in paragraph (3A), for the words "equal to half the period for which the licence was originally granted" the words "not exceeding the period prescribed for the renewal of prospecting licence under sub-section (2) of section 7 of the Act, or the period for which an application is made, whichever is less" shall be substituted.

(vi) in FORM H, after item 7, the following items shall be inserted, namely :—

"7A. The details of the area and the minerals in each State for which the applicant holds prospecting licence on the basis of information supplied by the licensee."

(vii) For FORM I, the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM I
(TO BE SUBMITTED IN TRIPPLICATE)

Government of.....

Received.....
at.....(Place)
on.....(date)
Initial of
Receiving Officer

Application for Mining Lease

[See rule 22(1) of the Mineral Concession Rules, 1960]

Dated the.....day of.....19...

To,

Through :

Sir,

I/We request that a mining lease under the Mineral Concession Rules, 1960 may be granted to me/us.

2. A sum of Rs. 500/- and Rs. 1,000/- being the fees in respect of this application and preliminary expenses respectively payable under sub-rule (3) of rule 22 of the said rule have been deposited (vide receipt Chulan No.....dated.... of the State Bank of India/Treasury.....)

3. The required particulars are given below :

(i) Name of the applicant with complete address.
Status of the applicant

(ii) Is the applicant a private individual/co-operative/firm/association/ private company/public company/public sector undertaking/joint sector undertaking or any other.

(iii) In case the applicant is,—

(a) an individual, his nationality, qualifications and experience relating to mining.

(b) a private company, the nationality of the members/Board of Directors of the company along with place of registration and copy of certificate of incorporation

(c) a public company, the nationality of its directors, the percentage of share capital held by Indian nationals along with its place of incorporation and copy of certificate of incorporation.

- (d) firm or Association, the nationality of all the partners of the firm or members of the association; and
- (f) a co-operative the nationality of non-Indian members, if any alongwith place of registration and a copy of the certificate of registration,
- (iv) Profession or nature of business of applicant
- (v) Particulars of documents appended :

Document	Reference					
(a) Mining dues clearance certificate						
OR						
(b) Affidavit in lieu of Mining Dues Clearance Certificate; subject to the production of mining lease dues, clearance certificate within the period of ninety days of making application.						
OR						
(c) Affidavit when not holding any mining lease.						
(d) Affidavit that up-to-date Income tax Returns as prescribed under the Income Tax Act, 1961 and that the tax due including the tax on account of self-assessment has been paid.						

(vi) Mineral or minerals which the applicant intends to mine						
(vii) Period for which mining lease is required						
(viii) Extent of the area for which mining lease is required						
(ix) Details of the area in respect of which mining lease is required						

District	Taluqa	Village	Khasra No.	Plot No.	Area	Ownership/Occupancy

(x) Brief description of the area with particular reference to the following :

- (a) Does the applicant have surface rights over the area for which he is making an application for grant of a mining lease.
- (b) If not, has he obtained the consent of the owner, and the occupier of the land for undertaking mining operation. If so, the consent of the owner and occupier of the land be obtained in writing and be filed.

- (xi) (a) the situation of the area in respect of natural features such as streams or lakes.
- (b) in the case of village areas, the name of the village, the Khasra number, the area in hectares of each field or part thereof applied for.
- (c) In case the area applied for is under forest, then the following particulars be given :
 - (1) Forest division, Block and Range
 - (2) Legal status of the forest. (mainly reserved, protected, unclassified etc.)
 - (3) Whether it forms part of a National Park or Wild-life sanctuary.
 - (4) Type and extent of vegetation in the area.

- (5) For areas where no forest maps or cadastral maps are available, a sketch plan should be submitted on scale showing the area applied for together with boundary, if any, of any other existing mining lease or prospecting licence area, if the area applied for has any common point or line with the boundaries of existing prospecting licence or mining lease areas.
- (vii) The area applied for should be marked on plans as detailed below:
- In case a cadastral Map of the area is available, the area on this map should be marked showing the name of the village, Khasra Number and area in hectares of each field and part thereof.
 - In the case of forest maps the area should be marked on the map showing the range and felling series.
 - In case neither cadastral nor forest maps are available, the area should be marked on a sketch plan drawn to scales showing on this plan all important surface and natural features, the dimensions of the lines forming the boundary of the area and the bearing and distance of all corner points from any important, prominent and fixed point or points.
- (No. 1(3)/68-MII Dt. 30-3-68)
- (xiii) Particulars of the areas mineral-wise in each State duly supported by an affidavit for which the applicant or any person joint in interest with him.
- already holds under mining lease
 - has already applied for but not granted;
 - being applied for simultaneously :
- (xiv) Nature of joint in interest, if any
- (xv) (a) Does the applicant hold a prospecting licence over the area mentioned at (xi) above ? If so, give its number and date of grant and the date when it is due to expire.
- (b) Has the applicant carried out the prospecting operations over the area held under prospecting licence and sent his report to the State Government, as required by rule 16 of the Mineral Concession Rules, 1960 ? If not, state reasons for not doing so.
- (xvi) Broad parameters of the mineral/ore body/bodies
- Strike length, average width and dip.
 - Wall rocks on hanging and foot wall sides.
 - Whether area is considerably disturbed geologically or is comparatively free of geological disturbances. (copy of geological map of the area is to be attached).
 - Reserves assessed with their grade(s) (chemical analysis reports of representative samples are to be attached)
 - Whether the area is virgin. If not, the extent to which it has already been worked. In case there are old workings, their locations are to be shown on the geological map of the area.
- (xvii) Broad parameters of the mine
- Proposed date of commencement of the mining operations.
 - Proposed rate of mineral production during the first 5 years (year-wise)
 - Proposed rate of production when mine is fully developed.
 - Anticipated life of the mine

(e) Proposed method of mining, *Underground or opencast*

(i) If underground, the method of approach to the deposit mineral/ore-whether through inclines or shafts.

(ii) If opencast, the over-burden to ore ratio and overall pit slope.

(f) Nature of the land chosen for dumping overburden/waste and tailings (that is type of land whether agricultural, grazing land, barren, saline land etc.) and whether proposed site has been shown on the mine working plan. Give also the extent of area in hectares set apart for dumping of waste and tailings.

(xviii) A mining plan whether duly approved by the Central Government. (to be attached with this application)

(xix) Manner in which the mineral raised is to be utilised

(a) (i) if for captive use, the location of plant and industry.

(ii) for sale for indigenous consumption.

(b) if for exports to foreign countries indicate.

(i) names of the countries to which it is likely to be exported where the mine is being set up on 100% export oriented or tied-up basis.

(ii) whether mineral will be exported in raw form or after processing. Also indicate the stage of processing, whether intermediate stage or final stage of the end-product.

(c) if it is to be used within the country, indicate—

(i) the industry/industries in which it would be used.

(ii) whether it will be supplied in raw form or after processing (crushing/grinding/beneficiation/calcing).

(iii) whether it would need upgradation and if so, whether it is proposed to set up beneficiation plant. Also indicate the capacity of such plant and the time by which it would be set up.

(d) in case of coal, or other high bulk minerals/ores details of existing railway transport facility available and additional transport facility, if any, required.

(xx) Name, qualification and experience of the Technical Personnel available for supervising the mines.

(xxi) (i) Financial resources of the applicant.

(ii) Anticipated yearly financial investment during the course of mine construction and aggregate investment upto the stage of commencement of commercial production.

(xxii) (a) Nature of waste water, (e.g. whether acidic). If so, expected PH value.

(b) The application form should be accompanied by a statement of the salient features of the scheme of mining. This should be generally on the lines of the "Project at a Glance" given in a mining feasibility report including features relating to the protection of environment.

I do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details including accurate plans and security deposit, as may be required by you.

Yours faithfully

Place :

Date :

Signature of the Applicant.

The topographical map of 1"=1 mile scale is obtainable from the office of the Survey of India, Hathibarkhala, Dehra Dun.

Detailed plan and topographical map are to be attached in triplicate with the original application in case mineral applied for is a scheduled mineral.

Note 1—If the application is signed by an authorised agent of the applicant, then the Power of Attorney should be attached.

Note 2—The application should relate to one compact area only, except when the application for mining lease is for an area already held under prospecting licence by the applicant.

Note 3—Such large size map, as may be available should be attached for proper demarcation of the area, specially when the area applied for is 40 hectares or less (No. MII-152 (58)|61 dt. 30-4-63)."

(viii) in paragraph 2 of FORM J,—

(a) Clauses (v) and (vi) shall be deleted.

(b) for clause (vii) the following clause shall be substituted, namely :—

"(vii) an affidavit, that upto date Income Tax returns, as prescribed under the Income Tax Act, 1961, have been filed, and the tax due, including the tax on account of self-assessment has been paid."

(c) after clause (x), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(xA) (a) Does the applicant continue to have surface rights over the area of the land for which he requires renewal of the mining lease.

(b) If not, has he obtained the consent of the owner and occupier for undertaking mining operations. If so, the consent of the owner and occupier of the land obtained in writing, be filed.

(xB) Particulars of the areas mineral-wise in each State duly supported by affidavit for which the applicant or any person joint in interest with him.

(a) already holds under mining lease ;

(b) has already applied for but not granted, or

(c) being applied for simultaneously.

(xC) a mining plan which shall include—

(a) the plan of the area showing the nature and extent of the mineral body, spot or spots where the excavation is to be done in the first year and its extent, a detailed cross-section and detailed plan of spot(s) of excavation based on prospecting data gathered by the applicant, a tentative scheme of mining for the period of the lease ;

(b) the details of geology and lithology of the area, the extent of manual mining and through machines ;

(c) annual programme and plan for excavation from year to year ; and

(d) the plan of the area showing natural water courses ; limit of reserved and other forest areas and density of trees, assessment of impact of mining activity on Forest, Land surface and Environment including air and water pollution, and details of the scheme for restoration of the same by afforestation, land reclamation, use of pollution control devices."

(ix) in Form K, in PART VII, after clause 11, the following clauses shall be inserted, namely :—

"11A. The lessee shall pay a wage not less than the minimum wage prescribed by the Central or State Government from time to time ;

11B. The lessee shall comply with provisions of the Mines Act, 1952 ;

11C. The lessee shall take measures for the protection of environment like planting of trees, reclamation of land, use of pollution control devices ; and such other measures as may be prescribed by the Central or State Government from time to time at his own expense.

11D. The lessee shall pay compensation to the occupier of the land on the date and in the manner laid down in these rules."

(x) in Form N, clause 4 shall be omitted.

Foot-note : The principal rules were amended earlier also. A list of notifications for such amendments is enclosed.

[F. No. 7(1)|86-M. VI]

THE LIST

1. Notification No. 1|34|71-M-6 dt. 21-5-73.
2. Notification No. M.II-152(37)|62 dt. 22-7-63.
3. Notification No. 1(34)|68-M.II dt. 23-5-70.
4. Notification No. 1(26)|71-M.VI dt. 14-2-72.
5. Notification No. 1(2)|68-M.II dt. 23-2-68.
6. Notification No. 1(3)|68-M.II dt. 30-3-68.
7. Notification No. M.II-169(44)|61 dt. 7-9-61.
8. Notification No. 1(22)|62-M.II dt. 18-7-63.
9. Notification No. 1(74)|75-M.VI dt. 2-5-79.
10. Notification No. 1(3)|68-M.VI dt. 17-1-69.
11. Notification No. 1(33)|67-M.VI (Vol. II) dt. 22-7-1971.
12. Notification No. M.II-169(44)|61 dt. 6-9-63.

13. Notification No. 1(3)/71-M.VI dt. 6-9-71.
14. Notification No. 1(51)/65-M.II dt. 26-2-69.
15. Notification No. M.II-152(11)/62 dt. 6-5-63.
16. Notification No. 3(51)/74-M.VI dt. 16-1-80.
17. Notification No. M.II-152(58)/61 dt. 30-4-63.
18. Notification No. M.II-152(33)/60 dt. 24-9-63.
19. Notification No. 1(26)/66-M.VI dt. 4-3-67.
20. Notification No. 7(4)/85-M.VI dt. 22-9-86.

अधिसूचना

सा.का.नि. 87(अ) :—केन्द्रीय सरकार खान और खनिज (नियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का 37) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 फरवरी 1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको

खान और खनिज (नियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का 37) प्रवृत्त होगा।

[फाइल स. 1(7)/84-एम-6]

टी. ए. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

G.S.R. 87(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Act, 1986 (37 of 1986), the Central Government hereby appoints the 10th February, 1987 as the date on which the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Act, 1986 (37 of 1986) shall come into force.

[F. No. 1(7)/84-M.VI]

T. N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

